the industrialisation of backward areas, a package of delicensing of industries was announced by the Government on 3rd June, 1988. This scheme exempted the industrial undertakings from the licensing provisions subject to certain investment limits, locational criteria, import content of raw-materials and the compulsory licensing list. The scheme is no longer relevant in the wage of the New Industrial Policy, July, 1991. There are no pending proposals under this scheme.

Contract between BBUNL and Essar India Ltd.

2032. PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd., entered into a contract with Essar India Ltd., a private concern for supply of 'Jongs' from Jessop's Works at a reduced rate;

(b) whether the contract was entered into without obtaining the recommendation of the Director (Finance), as is required under the rules;

(c) whether the then Director (Production) was released from the services of Jessop & Co. Ltd. so as not to reveal the irregularity in this contract; and

(d) fi so, what acton has been taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) M/s. Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd. (BBUNL) have not entered into any contract with Essar India Limited. However, Jessop & Company Limited, a subsidiary of Bharat Bhari Udyog Nigam Limited entered into a contract with Essar Steel which is a division of Essar Gujarat Limited for supply of a package of bridge for cranes including Tongs and electrical drives at competitive price. No separate contract was entered into for supply of Tongs. The contract was approved by Director (Finance) and Managing Director, Jessop & Company Limited.

(c) and (d) The person who was then Director (Production) of Jessop and Company Lmited continues to be the Director (Production) even now.

गुजरात में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

2033. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में केन्द्रीय सरकार के किन-किन सार्वजनकि क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की कमी हुई है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप इन उपक्रमों की कार्यकुशलता और लाभ में वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन उपक्रमों की कार्य कुशलता और लाभ को और अधिक बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 31 मार्च, 1992 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे दो उद्यम नामश: इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स लि० और नेशनल टेक्सटाईल कारपो० (गुजरात) लि० थे जिनके पंजीकृत कार्यालय गुजरात में थे । पिछले तीन वर्षों के दौरान सकल परिसम्पत्ति के रूप में या ऋणों

अथवा, सामान्य शेयरों के रूप में इन उद्यमों के निवेश में कोई कमी नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) निवल लाभ/हानि और उत्पादन मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(लाख रुपयों में)

सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	निवल लाभ/हानि		
	1991–92	1990–91	1989–90
इंडियन पेट्रोकैमिकल्स लि० . . .	5502	5725	8124
नेटेका (गुजरात) लि० . . .	(–)3713	(–)2195	(–)2788

(करोड़ रुपयों में)

सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	उत्पादन मूल्य		
	1991–92	1990–91	1989–90
इंडियन पेट्रोकैमिकल्स लि० . .	1671	1100	1006
नेटेका (गुजरात) लि० . . .	118	117	110

(घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है । कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिये संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा उद्यमों द्वारा उधन विशेष की आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जाती है। उठाए गए कुछ कदम हैं : आधुनिकीकरण करना और पुनर्स्थापन योजना बनाना, वित्तीय, प्रबंधकीय और संगठनात्मक पुनर्गठन करना, उत्पाद मिश्र में परिवर्तन करना, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना इत्यादि ।

Representations from M.Ps.

2034. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of letters/representations/memoranda received by him from the Members of Parliament during the last six months;

(b) what is the number of cases where the acknowledgement was sent within a period of fifteen days and the number of those cases where final replies have yet not been sent;

(c) what are the reasons for not sending any acknowledgement within fifteen days and the final reply within three months; and

(d) what is the number of officers who have been found guilty for delay in sending acknowledgement and for delay in sending final replies and for not replying the letters as well as misleading the Members of Parliament and what punishment has been awarded to them?